DR. ARUN KUMAR SARMA (Assam): Mr. Chairman, Sir, thank you very much for giving me this opportunity to associate myself with this Special Mention. The issue of fake currency is a very serious threat to the economy of our country. It has a serious impact on our economy. The machine used for detection of fake currency is out of reach of the common man. That is one of the reasons that fake currency is being circulated throughout the country, especially in the North-Eastern region. I am laying emphasis on the North-Eastern region because I represent that area. The North-Eastern region has become a dumping ground for fake currencies. There is sufficient proof that the ISI is involved in dumping of fake currencies in this region. Last year, there was a news item in different newspapers that the ISI is pouring a huge quantity of fake currency from abroad into the North-Eastern region. Another dimension of the problem is that there is an acute shortage of fresh currency, new notes in the North-Eastern region. For the last 4-5 years, the RBI has not replaced the old, soiled, unhygienic, depleted notes, in the region. Sir, it reflects on the prestige of the country. I have got samples of these old, soiled, unhygienic, depleted notes with me. The hon. Finance Minister is also here; I would like to show these notes to this august House. Such notes have not been replaced for the last 4-5 years. These are still in circulation. Some of the notes are even beyond recognition; as to which denomination do they belong; whether they are one-rupee notes, or two-rupee notes, or five-rupee notes. Even the fifty-rupee notes are in a very depleted condition. I hope, the hon. Finance Minister will take adequate steps to direct the RBI to replace all such soiled notes. If a tourist comes to India and handles such type of notes, it reflects on the image of the country. I hope, the Finance Ministry would take this matter seriously and would see that these notes are be replaced immediately.

Removal of Jhuggi clusters with the help of bulldozers resulting in hundreds of poor people becoming homeless

श्रीमती सरोज दुबे (बिहार) : सभापति महोदय, आपने मुझे गरीब और शोषित लोगों की समस्या उठाने के लिए समय दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

आजादी के 50 साल बीत जाने के बाद भी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को आज भी छत जुटा पाने की व्यवस्था नहीं हो पाई, यह बड़े अफसोस की बात है। आश्रय की तलाश में उसे जहां कहीं जगह मिलती है वह वहां अपना सिर छिपा लेता है और यह साजिश

भी नहीं है और न कोई यह सियासी चाल ही होती है, यह तो गरीब जो दिन भर मेहनत करके आता है उसको सोने के लिए एक छत की तलाश होती है और उसी से झुग्गी और झोंपड़ियों की बस्ती बन जाती है। महोदय, जब कभी किसी नगर के सौंदर्यकरण की बात उठती है या उसकी सफाई की बात उठती है या फिर उद्योगीकरण की बात उठती है तो बुलडोजर का रुख झुग्गियों की तरफ मोड़ दिया जाता है और बिना किसी पूर्व सूचना के हजारों-हजार झोपड़ियों पलक झपकते ही ध्वस्त कर दी जाती हैं और उससे हजारों-हजारों लोग बेघर हो जाते हैं, केवल बेघर ही नहीं होते साथ ही साथ उनका रोजगार भी छूट जाता है। बड़ी मेहनत करके अपने कमाए हुए पैसे से पेट काट-काट करके गरीब एक टीन की छत्त डालकर या टाट का बोरा लगाकर या प्लास्टिक शीट लगाकर किसी तरह से एक छत जुटाता है और उसके अंदर उसकी छोटी सी गृहस्थी मगर उसके लिए बड़ी कीमती होती है, जिसमें उसके पास कुछ एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं, कुछ चीथड़े कपडे होते हैं, लकड़ी और कोयले का एक चूल्हा होता है और अचानक बुलडोजर उनका यह सब कुछ पल भर में स्वाहा कर देता है और वह बेरोजगा होकर अपने परिवार के साथ दर-दर पर भटकने के लिए मजबूर हो जाता है। इन विस्थापित लोगों में कोई पूंजीपति नहीं होता, कोई बड़ा आदमी नहीं होता। इसमें आदिवासी, किसान, रिक्शा वाला, सफाई वाला, बोझा ढोने वाले ये गरीब शोषित और दलित और गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले होते हैं। महोदय, यह दिन भर मेहनत करता है तो दिल्ली साफ रहती है, जब यह दिन भर मेहनत करके बड़े-बड़े भवन बनाता है तब आज सारी दिल्ली बड़े-बड़े भवनों से सुसज्जित हो सकी है। जब यह दिन भर कारखानों में काम करता है तब कपड़े बनते हैं। जब ये दिन भर हमारे गली-कूचों को साफ करते हैं तभी हम गंभीर बीमारियों से बचते हैं और यही मेहनत करने वाला और यह परिश्रम करने वाला और फिर यह आधा पेट रोटी खाने वाला जब किसी तरह से एक झुग्गी का इंतजाम कर लेता है तो सरकार बड़ी बे-रहमी से उसकी झुग्गी पर बलुडोजर चला देती है। तो महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि गरीबों को भी इस देश में जीने का अधिकार है। कोई भी झुग्गी में नहीं रहना चाहता, कोई भी झोंपड़ी में नहीं रहना चाहता। बरसात के दिनों में उसकी टूटी छत से पानी झडता है और नीचे से भी पानी बहता है, गरमियों के दिनों में उसमें लू के थपेड़े आते हैं। इस तरह की झुग्गियों में कोई नहीं रहना चाहता। मगर उनकी मजबूरी है क्योंकि आजादी के 50 साल बाद भी उनको हम छत नहीं दे पाए। अगर वह किसी तरह से झुग्गी का निर्माण कर लेता है तो उसके लिए हम बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए उसकी झुग्गी को तोड़ने का काम बड़ निर्ममतापूर्वक करते हैं। महोदय, यह नियम है कि जब किसी की झुग्गी-झोपड़ी को हटाया जाए या किसी को विस्थापित किया जाए तो उसको उसकी पूर्व सूचना दी जानी चाहिए और उसके लिए कोई

वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। उसको उचित दर पर मुआवजा दिया जाना चाहिये। वजीरपुर दिल्ली का औद्योगिक नगर है जहां पर 40 हजार झुग्गी-झोपड़ियां हैं। ये रेलवे की पटरी के किनारे बसी हुई बस्ती है। इनको हटाने की कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई और वहां पर बुल्डोजर भेज दिया गया। बुलडोजर से वहां के बच्चों में और लोगों में बहुत खौफ पैदा हो गया। जब वहां पर भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री वी.पी.सिंह और हम लोग पहुंचे तो वहां पर सचमुच में बड़ा दर्दनाक और दहशतभरा माहौल था। भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री वी.पी.सिंह के लम्बे धरने के बाद उनको उजाड़ने का काम रोका गया। अभी तक उनको वहां से हटाने का काम रुका नहीं है वह किसी तरह से टल गया है। महोदय, वहां पर जो गरीब आदमी रहते हैं वे खुद अपनी समस्याओं से परेशान हैं। वे रेल की पटरी के किनारे रहते हैं और रात के समय बीसों बार रेलें वहां से निकलती हैं।जब वहां से रेलें निकलती हैं तो झुग्गियां कांप उठती हैं, उनके बच्चें वहां खेलते रहते हैं वे भी दहशत में रहते हैं क्योंकि कभी भी दुर्घटना हो सकती है आखिर वे लोग जायें तो कहां जायें। जहां पर उनको रोजगार मिल गया, आश्रय मिल गया वहां पर उन्होंने झुग्गी बना ली। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि जब 25 साल से वे लोग वहां रह रहे हैं आपके अधीन एक विभाग है जिसका काम अनधिकृत कब्जों को रोकने का है तो उसने अनधिकृत कब्जा क्यों होने दिया? जिन लोगों ने पिछले 25 साल से कब्जा कराया है वे लोग कहां है? उनको क्यों नहीं ढूंगा जाता है? उन्होंने पहले क्यों कब्जा करने दिया ? आज अगर वह झापेड़ी बनाकर अपना सिर छिपाना चाहते हैं तो उनकी झोपड़ियों को तोड़ने की साजिश क्यों की जा रही है? वजीरपुर इंडस्ट्रियल इलाका है। वे लोग वहां पर विभिन्न उद्योगों में काम करते हैं। आप कहते हैं कि हम इनको यहां से हटाकर शहर के बाहर जगह दे देंगे। अगर आप उनको शहर से बाहर जगह दे देंगे तो वे वहां पर क्या काम करेंगे। केवल सिर छिपा लेना ही काफी नहीं है, अपना व अपने परिवार का पेट पालना भी जरूरी है। ये लोग सिर छिपाने के लिए ही गांवों से शहर में नहीं आये हैं. अपना पेट भरने के लिए यहां पर आये हैं। इसलिए आप उनको ऐसी जगह पर भेजिए जहां पर उनके लिए रोजगार की व्यवस्था हो सके। सभी को जीने का, रहने का और भोजन का मौलिक अधिकार है। 1996 में सुप्रीम कोर्ट जस्टिस कुलदीप नैय्यर की खण्डपीठ ने यह आदेश दिया था कि जब भी किसी झुग्गी-झोपड़ी को तोड़ा जाये तो उसके पहले उसकी वैकल्पिक व्यवस्था की जाये। बिना वैकल्पिक व्यवस्था के झुग्गी तोड़ना कोर्ट की अवमानना है। माना कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है लेकिन इसके पहले का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी साथ में मौजूद है कि उनके लिए रहने की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। आज जहां पर भी देखिए वहां पर बुलडोजर भेज दिया जाता है। ऐसा लगता है कि गरीबों को बिल्कुल जड़ से साफ कर दिया जाएगा। जब वोट लेने की जरूरत होती है तो

सारे नेता वहां जाकर खडे हो जाते हैं। और आज उनके सिर पर बुलडोजर का खौफ है तो कोई उधर रूख नहीं कर रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहती हूं कि वह कुछ मानवीय रुख अपनाये। वे भी इस देश के नागरिक हैं, वे भी इस देश में काम करते हैं। अगर वे न हों तो हम साफ कपड़े नहीं पहन सकते हैं, अगर वे न हों तो हमारी सड़कें साफ नहीं हो सकती हैं, गली- कूचे साफ नहीं रह सकते हैं। लोग कहते हैं कि ये झुग्गी वाले गंदगी करते हैं। महोदय, दिल्ली में रोजाना टनों कचरा निकलाता है यह झुग्गी-झोपड़ियों से नहीं निकलता है। यह सभ्रान्त कालोनियों में रहने वाले लोगों के घरों का कचरा होता है, यह मध्यम वर्गीय लोगों के धरों का कचरा होता है और इसको वे अपने सिर पर ढो कर फेंकते हैं। ये झुग्गी-झोंपड़ी वाले ही वहां पर सफाई करते हैं। इसीलिए मैं यह कहना चाहती हूं कि इन गरीबों के साथ मानवीय रुख अपनाया जाए और इनको उजाड़ने से पहले पूर्व सूचना दीजाए। इनके रहने की वैकल्पिक व्यवस्था ऐसे स्थान पर की जाए जिससे कि ये रोजी-रोटी कमा सकें और इनको रोजगार के अवसर मिल सकें। साथ ही साथ इनके बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूलों की व्यवस्था होनी चाहिये। स्कूलों और घरों में पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। उनके लिए राशकार्ड की और परिचय पत्र की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे की अगली बार उनको वहां से न उजाड़ा जा सके। जिन लोगों ने उन्हें 25 साल तक बसाने में पैसा लिया है, जो माफिया हैं, जिन अधिकारियों ने पैसा लिया है और अब वे ऊंची कुर्सियों पर चले गये हैं, आप जरा उनकी भी तलाश करिये। आप यह भी पता लगाइयें कि कैसे इतनी झुग्गी-झोपड़ियां बन गई? आप इन लोगों की रहने की वैकल्पिक व्यवस्था करिये। बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़े महलों में, अट्टालिकाओं, में एयर कंडीशन कमरों में रहें, इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये गरीब लोग भी इस देश के नागरिक हैं, ये लोग दिन भर मेहनत करते हैं,ये भी इस देश के निर्माण में अपना खून पसीना बहाकर मदद करते हैं। ये इस देश की सुन्दरता को बढ़ाते हैं। गरीबी कभी सुन्दर रुप नहीं देती है, किसी गरीब में सुन्दरता दिखाई नहीं देती है इसलिए आपको गरीबों के घरों को सुन्दर बनाना होगा। इस आजाद देश के वे भी एक नागरिक हैं, उनके घर के लोगों ने भी आजादी में कुर्बानियां दी हैं इसलिए उन्हें भी जीने का अधिकार दिया जाये। नये लोग शहरों में आते जा रहे हैं। सरकार ने घोषणा की कि एक करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। यह सुनकर गांव का नौजवान शहरों की ओर भाग रहा है कि शहर में एक करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। आर्थिक उदारीकरण की नीति के कारण लोग भागे चले जा रहे हैं इसलिए गांवों में आप सुधार करिए, गांव में स्वरोजगार के अवसर प्रदान करिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : बस हो गया। श्री रमा शंकर कौशिक।

श्रीमती सरोज दुबे : गांव में लोगों को काम करने का मौका दीजिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करती हूं। धन्यवाद।

श्री रमा शंकर कौशिक (उत्तर प्रदेश) : महोदय, श्रीमती सरोज दुबे ने जिस समस्या की ओर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित किया है,उससे मैं स्वंय को संबद्ध करता हूं । इस समस्या के कई आयाम हैं । बेरोजगारी की समस्या, गांव से पलायन, विभिन्न सरकारों और जो विभिनन संस्थाएं हैं - चाहे वह नगर निगम हो, चाहे नगर पालिकाएं हों - उनकी संवेदनशीलता का प्रश्न भी इसके साथ जुड़ा हुआ है । ऐसा लगता है कि हमारी सरकारें संवेदनशीलता के मामले में बिल्कुल पिछड़ती जा रही है और किसी भी प्रकार से वह गरीब के प्रति या ऐसे लोगों के प्रति-जो खुली छत के नीचे रहने के लिए मजबूर हैं, जो टिन या प्लास्टिक की चादरों के नीचे रहने के लिए मजबूर हैं - उनके प्रति अपने किसी कर्तव्य को वह नहीं समझती । महोदय, इसमें कोई शक नहीं कि जहां तक एनक्रोचमेंट का सवाल है- चाहे वह नगर पालिका । की जगह हो, चाहे कोई सरकारी क्षेत्र हो या चाहे रेलवे लाइन का सवाल हो – वहां पर एनक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए । उसके पक्ष में हम लोग नहीं हो सकते, होना भी नहीं चाहिए लेकिन उसकी व्यवस्था तो आपको करनी पड़ेगी । जब हमारे गांवों से पलायन हो रहा है, वहां से लोग शहरों की ओर भाग रहे हैं क्योंकि वहां रोजगार नहीं है – हालांकि यहां भी रोजगार की व्यवस्था नहीं है लेकिन फिर भी उसे यहां दो जून की रोटी मिल जाती है । इसलिए केन्द्रीय सरकार का राज्य सरकारों का या जो भी संस्थाएं हैं - चाहे वह नगर निगम हो, चाहे नगर पालिकाएं हों - उनका भी यह कर्तव्य बनता है कि वे उनके रहने की ठीक से व्यवस्था करें और जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था न हो, तब तक उनको इस प्रकार से उजाड़ना बिल्कुल अमानवीयता है, इस प्रकार से उनको उजाड़ना किसी भी तरह से संवेदनशीलता का दर्शन नहीं कराता । श्रीमन्, मैं सरोज दुबे जी ने जो बात रखी है, उससे स्वयं को संबद्ध करते हुए आपके माध्यम से दस सदन से,सरकार से और दूसरी भी सरकारों से – जो इन बातों के लिए जिम्मेदार हैं - अपील करना चाहता हूं कि वे इस सबंधं में संवेदनशील हों और जब तक ऐसे लोगों को बसाने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था न हो, तब तक इस प्रकार बिना नोटिस के और बिना जानकारी के उनको उजाड़ना बिल्कुल अमानवीयता है, इस बात का ध्यान रखें । धन्यवाद ।

SHRI JIBON ROY (West Bengal): Sir. I associate myself with this.

MR. CHAIRMAN: No. Your party Member will speak. That is all right.

SHRI SHANKAR ROY CHOWDHURY (West Bengal): Mr. Chairman, Sir, 1 associate myself with the Special Mention made by hon. Smt. Saroj Dubey. This reflects the problem of rehabilitation. We have a growing urban sprawl. It is not confined to Delhi alone, but it is also there

throughout the country. I would urge the Government that it must not only take the proper, short-term measures that the hon. Members have pointed out but it must also have a look at the long-term economic policies, by which industries, particularly under the new regime, the liberalised regime, are being concentrated in those favoured areas where the so-called infrastructure exists. Unless industries are dispersed and the means of livelihood are created in villages,this flow to cities will continue. India is a country where 80 per cent of the people live in the villages. It is also a forecast that within the first quarter of this century, up to 30 per cent of our people will be living in towns. So, I urge the Government to bear this in mind. Please not only plan for the short-term, immediate measures to be taken but also, on a long-term basis, see that, with the industrial policy you are following, the centres of growth are spread throughout the country and ensure that a degree of humanism is there when encroachments are vacated.

SHRI EDUARDO FALEIRO (Goa): Sir, I associate myself with the Special Mention made by Smt. Saroj Dubey.

The first point I want to make is that there should be, in such cases, no eviction without settlement, and the settlement should be at a place where the poor people, the miserable people who live in slums, have employment oportunities. These words are mild, compared to the words used in the National Housing and Habitat Policy. I have this document here with me. This document was brought out by this Government in furtherance, as it says, of the NDA's National Agenda for Governance. It states here in the very first paragraph:

> 'Mere lip-service will not do. What is required is a housing revolution."

Is this the housing revolution? When people do not get houses and when their wives and children do not have even the foothpath to live on, they go and occupy land and build their own shelter. This is happening not only in this country but all over the world. The policy makers at the global level have a global consensus that this is something which is a human problem. There should not be eviction without proper settlement. This is a global consensus which exists everywhere in Asia, in Africa and in Latin America, in particular. This is point number one.

Secondly, why are people living in slums?

The Minister is here. That is good. The Minister will reply to this, and I will be very happy.

People live in these miserable conditions. This Housing Policy says:

" 'Like beasts' words even beasts would protest."

That is what the housing policy says in the very first paragraph. Why are our co-citizens living like this? They live like this because there is no employment. Basically, this is the result of the migration of people from rural areas to urban areas. What is happening is that in rural areas, employment opportunites are falling completely. The development is decreasing. In the 1980's, the rate of growth in the rural areas was 3.1 per cent, as per the Planning Commission. Now, in the last couple of years, it has been 1.8 per cent. Now, the employment is decreasing to such an extent that when the Congress left the Government in 1995-96, the rural poverty was 38 per cent, and it has now grown to 45 per cent. I am mentioning about the rural poverty. I am quoting the figures given by the Member of the Planning Commission, Dr. S. Gupta, in public, a couple of months ago. This is the position. Therefore, the first thing that is required is to increase the number of houses. You say here, if I am not mistaken, in paragraph 1.7 of this document:

"Two million units will be created, built by the year."

I want to know from the hon. Minister what progress has been made in this regard.

Number two, in this Budget, the allocation for rural development, everything concerning rural development, the Rural Development Department itself, has been slashed down in a manner which, I feel, is brutal. There is a sharp slashing down of all projects of rural development, including self-employment and employment in the rural areas. That is why these things are happening. Therefore, we have to pay attention to the fact, that this imbalance which is growing between the rural areas and the urban areas in terms of growth, development and employment, is growing very fast because of the manner in which our new economic policies are being implemented. Therefore, I appeal here to the Government:

Number one, increase your Budget allocation for the Government programmes for employment in the rural areas at a faster rate.

Number two, increase the housing, particularly the housing for the poor people. Let us see what you have done about your plan for 2 million units per year. The hon. Minister will be able to tell this to us.

Number three, please implement what you say here in the beginning of paragraph 5.7 of the Policy. You say:

"Slum improvement/upgradation"

Instead of improving and upgrading the facilities which are practically nil in slums, you are just destroying them and sending the people away. There is a sharp contradiction between the words and the action on the ground. Therefore, I request that these things should be done. The first thing is: No demolition without proper settlement.

Thank you.

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बगांल) : माननीय सभापति महोदय, मैं श्रीमती सरोज दुबे ने जो विशेष उल्लेख किया है, उससे अपने आप को सम्बद्ध करती हूं। हमारे समाज में, हमारे महानगरों में, विशेषकर जो झुग्गी-झोपड़ियों में रह रहे हैं, वे वास्तव में हमारी सरकार की गरीब विरोधी आर्थिक नीतियों का परिणाम हैं और ये झुग्गी-झोपंडियां सरकार की आंखों में आंखें डालकर बार-बार यह बताने की प्रयास करती हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं के तमाम सपनों के विरूद्ध, उनकी तमाम कल्पनाओं के विरुद्ध हमारी आज तक की सरकारों ने जो नीतियां अपनाई, उन नीतियों की वजह से हमारे देश का आम आदमी और हमारे देश की बहुसंख्यक जनता, आज हम देख रहे हैं, एक इसांन के लिए जो मूलभूत जीने के अधिकार होते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, उनसे भी वंचित है।

माननीय वित्त मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं इसलिए मैं विशेषकर उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि क्या कभी हमारी सरकार ने उन आर्थिक नीतियों की पड़ताल की है कि वे कौन सी नीतियां हैं जिनके कारण न सिर्फ गांवों मे बल्कि शहरों में भी गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही है । महोदय, हमारे वत्ति मंत्री जी जिस विश्वव्यापीकरण की बात करते हैं, उदारीकरण की बात करते हैं उन्हीं के संबंध में पिछले इस वर्षो के आंकड़े हैं, कि इन उदारीकरण की नीतियों की वजह से गांवों में बहुत ज्यादा गरीबी बढ़ी है और गांवों में रोजगार के साधन बहुत कम हो गए हैं। हमारे मंत्री जी हमको कुछ बोल रहे थे लेकिन मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या यह सर्वे सही नहीं है? खुद विश्व बैंक ने सर्वे करके हमें रिपोर्ट में बताया है कि उनके उदारीकरण तमाम नुसखे, उनके ढांचागत समयोजन के तमाम नुसखे

विकासशील देशों की गरीबी दूर करने में ना काफी हैं और असफल साबित हुए हैं। इसके बावजूद उन्हीं उदारीकरण की नीतियों की ओर हमारी सरकार अग्रसर हो रही है। परिणाम यह हो रहा है कि गांव में रोजगार के साधन बिलकुल कम हो गए। प्रेमचन्द ने गोदान में जिस होरी की कल्पना की थी और होरी का बेटा गोबर शहर में रोजगार की तलाश में आया था। आज ऐसे गोबरों की संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि होरी तो हो गया खेत मजदूर और गांव में काम न मिलने के कारण उसका बेटा चला गया शहर में। हमारा आज का यह यथार्थ गांव से आए उन गोबरों का यथार्थ है। इसलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि कृपया वे अपनी नीतियों को बदलें। आज दिल्ली की हालत यह कि यहां पर चालीस फीसदी से अधिक आबादी झुग्गी-झोपड़ियों में रहती है। इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हमारे देश की राजधानी में चालीस फीसदी से अधिक आबादी झुग्गी-झोपड़ियों में रहती है। किसी भी तरह की हमदर्दी का हाथ सरकार इनकी ओर से नहीं बढ़ाती है बल्कि बुलडोजर चलाकर इनको यहां से खदेड़ना चाहती है। यह कौन सी नीति है? यह मानवीय नीति नहीं है। आप उनको रोटी नहीं दे सकते, रोजगार नहीं दे सकते। सिकी तरह अगर वे अपना पेट भरने के लिए काम करना चाहते हैं तो सरकार उनको उजाड़ने का काम करती है। अगर कोई क्लिंटन महाराज आता है तो वहां पर्दा लगा दिया जाता है , उनको उजाड़ा जाता है। महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूं कि पश्चिमी बगांल में किस तरह गरीबों की हमदर्द सरकार है और किस तरह शहरों के अदंर भी ....

श्री नरेन्द्र मोहन : मीटिंग में क्या हुआ ? ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सरला माहेश्वरी : आप चुप रहिए। शहरों के अंद हम लोग बस्तियों का विकास कर रहे हैं। गरीबों के लिए रहने का स्थान बना रहे हैं। आप भी हमें कोई उदाहरण बता दीजिए कि हमने यह किया है। महोदय, यह बहुत बड़ी मानवीय समस्या है और आप इसको इस तरह मत देखें। यह मनुष्य के जीने का एक अधिकार है। कम से कम आप अपनी संवेदनशीलता को इतना तो बनाइए। आज मीडिया का बहुत प्रकोप हो रहा है और वह चाहता है कि मनुष्य की संवेदनशीलता खत्म हो जाए, हम मनुष्य की तरह सोचना बन्द कर दें और हमारा विवेक खत्म हो जाए। यह हमारे हिन्दुस्तान की परम्परा नहीं है। मनुष्य होने के नाते यह संवेदनशीलता अहम है, आवश्यक है। इसलिए इस संवेदनशीलता को जगाइये। आप दिल्ली में अमानवीय काम कर रहे हैं इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस तरह से गरीबों की झुग्गी-झोपड़ियों को न उजाड़ें। अगर आदमी का सपना ही मर जाएगा तो वह जिंदा नहीं रहेगा। मैं सरकार से जानना चाहूंगी कि उसकी नई आवास नीति क्या है?

1.00 P.M

सरकार गांव में नई-नई योजनाएं बनाती है लेकिन उन पर काम नहीं होता है । मैं राजस्थान में उदयपुर गई थी । वहां जाकर मैंने देखा कि मकान के नाम पर एक चबूतरा सा खड़ा कर दिया है । उनमें न दरवाजे हैं, न खिड़की है । आवास योजना के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं लेकिन उसके कोई सुपरिणाम नहीं निकल रहे हैं । सरकार अपनी आवास नीतियों को पलट कर देखें कि किस तरह से उनका रुपया खर्च हो रहा है, गरीबों के लिए किस तरह और मध्यम वर्ग के लिए किस तरह । मकान बनाए जाते हैं । अगर आप गरीब विरोधी नीतियों को बदलेंगे तभी वास्तवर में वहीं इस समस्या का समाधान होगा । इसलिए मैं यह कहना चाहूंगी कि सरकार अपनी आर्थिक नीतियों को बदले और गरीबों के पक्ष में आर्थिक नीतियों लागू करे ।

MR. CHAIRMAN: Shri T.N. Chaturvedi.

SHRI T.N. CHATURVEDI (Uttar Pradesh) : Sir, the Minister is responding.

MR. CHAIRMAN: You are not speaking?

SHRI T.N. CHATURVEDI: I will not speak, Sir.

MR. CHAIRMAN: There is one more Member, Mr. Samadani. Let him also speak. Then I will call the Minister. Mr. M.P.A. Samad Samadani.

SHRI M.P.A. SAMAD SAMADANI (Kerala) : Mr. Chairman, Sir, the hon. Member, Shrimati Saroj Dubey, has drawn the attention of this House to a very serious issue. Nowadays, so many news-items are appearing in the Press regarding the atrocities committed on the" poor who reside in such areas. Sir, instead of considering the seriousness of the issue and instead of considering those factors which lead to this kind of a state of affair, the Government agencies are acting without any kind of mercy being shown to the poor people. The Government should show some compassion towards them. We do not blame the present Government for this situation. All these issues have not arisen after the present Government came into power. But my request to the Government is....*(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, it is already one o' clock. We will continue. After Mr. Samadani, the Minister will say something and then we will adjourn.

SHRI M.P.A. SAMAD SAMADANI. The present Government could have acted with some compassion. That is my suggestion. The point is that there is poverty. We are not able to settle our people in our own land. That

is the problem. But there is a wide area of land lying vacant. If the Government had a concrete policy, a positive policy, they could have utilised this land for housing and rehabilitating these people. But that has not been done. The other problem is that of unemployment. The most important cause is urbanisation. The country cannot afford this kind of speedy urbanisation. Why is this happening? Nobody has attended to this very important question. The Father of the Nation, Mahatma Gandhi, saw Indian life in the villages, in the rural areas. Now, instead of that, we have to turn to the cities to see India. Why is such a state of affairs prevailing? It is because of the fact that the village life is losing its economic support. Whatever is produced by the poor farmers, is sold at a distress price. There is a heavy fall in prices. So, the poor people are migrating to the cities. In such circumstances, they cannot live peacefully in the villages. They cannot stand on their own legs in the villages. One thing is very common in India, that is, the mother coming to the city in search of work, tying her own saree to the branch of a tree and making a cradle out of that for her child. This type of situation is there. Instead of protecting her life, instead of giving her support, instead of paying some attention to her with a humanistic view-point, we are evicting her. My suggestion is that instead of evicting her, we should go to that mother and seek her pardon. Instead of evicting them from such areas, the Government should pay attention to strengthen the economic background of the village life. That will be the only solution to get rid of this problem. There are so many environmental problems also. I am not going into those things because I do not want to take much time of the House. If we are compelled to evict them, why can't the Government give them enough time? Why is the Government not giving them a chance to build their own houses in the rural areas or in the suburbs of the cities? In a metropolitan city like Delhi, there are suburbs which can be utilised for this purpose and some employment can also be generated. But, all of a sudden, on one fine morning or at mid-night, going with the bulldozer, evicting our own people, is a cruelty done by the Government to its own citizens. I request the Government to protect these people from such situations. Thank you.

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI JAGMOHAN): Sir, I am responding, because I think, there is a lack of information, or deliberately, the same thing is being said. Since 1998, I have been giving an alternative accommodation to every squatter who has been removed from

the land and I have made a number of statements in the Press. During this period, 10,000 squatters have been resettled and everybody has been given an alternative land. You can go and see it in Rohini, you can go and see it in South Delhi, you can go and see it in Narela. The issue is, they themselves asked for these valuable lands, and we are settling them in accordance with a scheme, a programme. I have made a number of statements that everybody is being resettled. The people have applied. They may have to make a little contribution. They have made the contribution.

I do not know why, over and over again, the same thing is repeated. We are giving that, and they are asking for the same thing, that is already given. I cannot understand this, except that it may be said for a certain other reason than merit. Therefore, I want to make this point very clear.

The second point is, it is not that we are just wanting to remove these people for the sake of removal. The issue is that certain schemes are required to be implemented. Now, take the Central Government Complex, a building from where these jhuggis are being removed during this week. The cost of escalation alone, because of the non-removal of these jhuggis during the last so many years is more than Rs.200 crores. Parliament should not have passed that project. They have passed the project, made the Budget provisions that you must construct this year. If there are squatters, then what do we do? We have to resettle them. So, they are being resettled in accordance with the programme which is started in public interest -resettlement of these poor people, implementation of the development schemes.

Then, there are certain other areas where these squatters cannot remain, on account of public interest. For example, if there are squatters, say 2000, in the All-India Institute of Medical Sciences complex itself, without any sanitary facilities, and if the Director of that Institute now comes to me and says, "Look, patients come here, and if these people continue to remain over here as they are, then they will only transmit infection to the patients. Do you want such a situation to continue?" So, all these people have been removed and given alternative accommodation in South Delhi, which is a very prime land, and in one area alone, the cost of resettlement is Rs.9 crores. In another area, it is Rs. 14 crores, and more than 10,000 squatters have been resettled. It is the cost of resettlement

alone, leave the valuable cost of land, which I am not counting. If I had sold this land, disposed of this land, I would have earned crores and crores of rupees.

Then another point that is being made is about employment. The reason is precisely the one which some hon. Members have given, the economic reason. My reason itself is an economic reason. If you make the process of migration from rural to urban as an employment-oriented migration, as a skill-oriented migration, it will benefit the economy. I am always resettling them in an area where there is scope for getting employment, a skill-oriented employment. For example, those who are going to Narela will have an opportunity to have a Narela industrial estate. They will become skilled workers. They will acquire some skill, instead of staying at a place having a nalla nearby and then competing among themselves, and they will be doing only menial jobs, cleaning utensils of the people. There is a scheme behind it. There is a thinking behind it. You go to Jehangirpuri. ...*(Interruptions)*.. Let me complete it. You go to Jehangirpuri and you can find all the people who were resettled by me when I was Lt. Governor; everybody is now earning. There are 10,000 families. Along with shifting the Subzi Mandi, I shifted the people there. Today, everybody is skill-oriented. A person is either a truck operator or a cleaner. A person is having either a scooter-parts shop or a motor-repair shop. Everybody is earning not less than ten thousand rupees a month. Everybody is sending his child to school. Everybody has got electricity, water, sewer. Do you want the people to stay where there is no ground for defecation? And they do defecate in the open. No sanitary facilities at all; no power, no water. What will be the future of their children? So, I think, there is lack of understanding of the entire issue, and there can be no better scheme. In fact, some of the reports of the United Nations themselves say that this is the best scheme that has been evolved. As you know, environmental upgradation is one of the achievements. Wherever it is possible to resettle them at the same place, they are not shifted. They are shifted only from unsuitable places; they are shifted only from the areas earmarked for schools, hospitals, roads, public projects, etc. They are only shifted from those areas.

There is a rationality behind it. I don't know why in the Press statements after statements are being published that they are being bulldozed and so on. There is no bulldozing like that. They are all resettled.

Thousands of trucks are given to them to go to the new sites. ... *(Interruptions)*...

श्रीमती सरोज दुबे : हम लोगों के सामने बुलडोजर आए। ...(**व्यवधान**)... पूर्वी दिल्ली और रोहिणी में हमारे सामने बुलडोजर आए और कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कि गई। मंत्री जी सुहाने सपने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री वी.पी. सिंह बीमारी की हालत में रोज एक एक झुग्गी-झोंपड़ी के सामने खड़े हो रहे हैं। मंत्री जी हाऊस को बता रहे हैं कि हमने वैकल्पिक व्यवस्था कर दी है। इतना बुरा हाल हो गया है झुग्गी-झोंपड़ी वालों का, चक्कर काट रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री संघ प्रिय गौतम : मंत्री जी का जवाब तो पूरा होने दीजिये। ...(**व्यवधान**)... बोलने दीजिये उन्हें । ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सरना माहेश्वरी : जवाब हो गया है। ...(**व्यवधान**)...

श्री संघ प्रिय गौतम : जवाब तो पूरा कर लेने दीजिये। ...(**व्यवधान**)... यह ठीक नहीं है। ...(**व्यवधान**)... बिहार जैसा यहां भी बनाना चाहते हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सरोज दुबे : हम लोगों ने अपनी आंखें से देखा है। ...(**व्यवधान**)... हम लोगों ने आन्दोलन में भाग लिया है। ...(**व्यवधान**)... बुलडोजर्स के सामने खड़े हुए हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सरला माहेश्वरी : आंखों देखे को झुठला रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री रामदेव भंडारी : (बिहार) गौतम जी क्या बिहार की बात करते हैं । ...(**व्यवधान**)...

श्री सुरेश पचौरी : अब उनको बोलने भी नहीं दिया जा रहा है। ...(**व्यवधान**)...

श्री रामदेव भंडारी : यह हमेशा सदन में हंगामा करवाते हैं। ...(**व्यवधान**)... यह इनकी आदत बन गई है। ...(**व्यवधान**)...

श्री संघ प्रिय गौतम : मंत्री जी का जवाब तो पूरा होने दीजिये। ...(**व्यवधान**)...

श्री रामदेव भंडारी : बार बार रिपीट कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Let the Minister reply. ...*(Interruptions)*... Let the Minister reply. ...*(Interruptions)*... He is not yielding. ...*(Interruptions)*... He has not yielded. ...*(Interruptions)*...Have you

yielded? ...*(Interruptions)*... He has not yet yielded. ...*(Interruptions)*... He wants to speak. ...*(Interruptions)*.... Let the Minister speak. ...*(Interruptions)*...Let the Minister speak. (Interruptions)...

श्री रामदेव भंडारी : बार बार अपनी बातों को दोहरा हरे हैं। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: He wants to say something. ...*(Interruptions)*... Let him speak ...*(Interruptions)*...

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Let him finish first. ...*(Interruptions)*...

श्री जगमोहन : मुझे सिर्फ एक बात कहनी है। ...(**व्यवधान**)... मैंने आपकी सारी बातें सुनी है। ...(**व्यवधान**)...

SHRTMATI AMBIKA SONI(Delhi) : You send a team of Members of Parliament to see the resettlement colony. ...*(Interruptions)*...Why are you not working in a transparent manner? ...*(Interruptions)*... You are trying to tell us something which is not the reality ...*(Interruptions)*...

श्री जगमोहन : जो बातें आपने कहीं हैं, मैंने सब सुनी हैं। मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि जो बुलडोजर की बात कह रहे हैं, बुलडोजर तो डिबरीज क्लीयर करने के लिए था। जो यह रेलवे एरिया वाली बात कह रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : उनको अपनी बात तो पूरी कर लेने दीजिये। ...(**व्यवधान**)...

श्री टी.एन. चतुर्वेदी : लैंड क्रेडिट वर्चू बना रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री जगमोहन : उस जगह से किसी को हटाया नहीं गया क्योंकि मैटर कोर्ट में है और प्रोसीडिंग्ज चल रही हैं। जैसे कोर्ट का आदेश होगा, वैसा किया जाएगा। इसलिए मैं उस प्वाइंट को यहां नहीं कहना चाहता हूं। जो बाकी प्वाइंट्स आपने रेज किये हैं, मैंने सब के जवाब दे दिये हैं। ...(**व्यवधान**)...

SHRI RAJU PARMAR: We are not satisfied with his reply.

MR. CHAIRMAN: This is not a reply. This is a Special Mention.

The House is adjourned for one hour.

The House then adjourned for lunch at fourteen minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at sixteen minuted past two of the clock, [The Vice-Chairman (Shri T.N. Chaturvedi) in the Chair]

THE VICE-CHAIRMAN(SHRI T.N. CHATURVEDI) : Now, we take up the Statutory Motions:

STATUTORY MOTIONS

I. ANNULMENT OF NATIONALISED BANKS (MANAGEMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) (AMENDMENT) SCHEME, 2000 PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA VIDE NOTIFICATION S.O. 58 (E).

AND

II. NATIONALISED BANKS (MANAGEMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) (AMENDMENT) SCHEME, 2000 PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA VIDE NOTIFICATION S.O. 59 (E).

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal): Sir, I move the following motion:

"That this House resolves that in pursuance of sub-section (6) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) (Amendment) Scheme, 2000 published in the Gazette of India dated the 20th January, 2000 *vide* Notification S.O. 58 (E) and laid on the Table of the House on the 14th March, 2000, be annulled.

That this House recommends to Lok Sabha that Lok Sabha do concur in this Motion."

I also move

"That this House resolves that in pursuance of sub-section (6) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) (Amendment) Scheme, 2000 published in the Gazette of India dated the 20th January, 2000 *vide* Notification S.O. 59 (E) and laid on the Table of the House on the 14th March, 2000, be annulled; and

That this House recommends to Lok Sabha that Lok Sabha do concur in this Motion."